आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में दमोह जिले में स्वदेशी महिला उद्यमिता की भूमिका

दिनेश कुमार नेमा[a1] एवं प्रियंका सेन[b]

[a]शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.), भारत
[b]महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.), भारत

सारांश

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें स्थानीय संसाधनों के उपयोग, स्वदेशी उत्पादन और महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया गया है। दमोह जिले जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक कृषि–प्रधान जिला है, इस अभियान के अंतर्गत स्वदेशी महिला उद्यमिता के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन दमोह जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में स्वदेशी महिला उद्यमिता की भूमिका का विश्लेषण करता है। जिले में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों कृषि–आधारित सूक्ष्म उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई–कढ़ाई, डेयरी एवं लघु व्यापार जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत गठित महिला समूहों ने स्थानीय संसाधनों पर आधारित उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इन समूहों ने पापड़, अचार, मसाला, आटा–दाल प्रसंस्करण तथा पारंपरिक वस्त्र निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमिता ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आय में वृद्धि तथा सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय समावेशन और ऋण सुविधा प्राप्त हुई, जिससे सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना संभव हो सकी। साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन विपणन की सुविधा ने स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाने में सहायता की। हालाँकि, पूंजी की कमी, विपणन नेटवर्क का अभाव, तकनीकी प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता तथा सामाजिक प्रतिबंध जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इसके बावजूद, स्वदेशी महिला उद्यमिता दमोह जिले में आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को गति प्रदान कर रही है।

कीवर्ड: आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वदेशी महिला उद्यमिता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्रस्तावना

आत्मनिर्भर भारत अभियान की परिकल्पना भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस अभियान का मूल आधार "वोकल फॉर लोकल" है, जिसके माध्यम से स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की इस प्रक्रिया में महिला उद्यमिता एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरकर सामने आई है, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में।

दमोह जिला जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का एक कृषि–प्रधान जिला है, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकास की संभावनाओं से परिपूर्ण है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन और लघु उद्योगों पर आधारित है। परंपरागत रूप से महिलाएँ घरेलू कार्यों तक सीमित रही हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं और सरकारी प्रोत्साहन के माध्यम से वे उद्यमिता की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ी हैं।

दमोह जिले में स्वदेशी महिला उद्यमिता का विकास स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर आधारित है। महिलाएँ खाद्य प्रसंस्करण (पापड़, अचार, मसाले), सिलाई–कढ़ाई, हस्तशिल्प, डेयरी उत्पादन तथा कृषि आधारित लघु उद्योगों के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं। विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को संगठित कर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में दमोह जिले की महिलाएँ न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर

[1]**Corresponding author**

रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में भी योगदान दे रही हैं। इस प्रकार, स्वदेशी महिला उद्यमिता आत्मनिर्भरता की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है।

साहित्य समीक्षा

- अत्मनिर्भर भारत अभियान (2020) भारत सरकार द्वारा 2020 में घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज का उद्देश्य कोविड–19 संकट के पश्चात अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और घरेलू उत्पादन को सशक्त बनाना था। यह पैकेज लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया गया।

- नीति आयोग (2021) इस रिपोर्ट में महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी बढ़े तो भारत की ळक्च में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। दमोह जैसे अर्ध–ग्रामीण जिलों में कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और बाजार उपलब्धता को महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है।

- वर्ल्ड बैंक (2021) में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी देश की दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति, उत्पादकता वृद्धि और सामाजिक स्थिरता के लिए महिलाओं की श्रम–भागीदारी (Female Labour Force Participation – FLFP) अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो राष्ट्रीय आय, घरेलू आय स्तर और मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

- डिजीटल इंडिया (2021) की रिपोर्ट में डिजिटल अवसंरचना, ई–गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और डिजिटल साक्षरता के विस्तार का विवरण दिया गया है। इसका एक प्रमुख आयाम ग्रामीण महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण है।

- मिनिस्ट्री ऑफ MSME (2022) में MSME क्षेत्र की संरचना, विकास, रोजगार सृजन तथा महिला–स्वामित्व वाले उद्यमों की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत में महिला उद्यमिता, विशेष रूप से सूक्ष्म (Micro) उद्यमों के माध्यम से, तेज़ी से उभर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

- नाबार्ड (2022) SHG & Bank Linkage Report भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group – SHG) आंदोलन की प्रगति, बैंक ऋण उपलब्धता, महिला भागीदारी और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि SHG मॉडल ग्रामीण महिला उद्यमिता का सबसे सशक्त और टिकाऊ माध्यम बन चुका है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. दमोह जिले में स्वदेशी महिला उद्यमिता की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. आत्मनिर्भर भारत अभियान का महिला उद्यमिता पर प्रभाव का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति

इस शोध में दमोह जिले की महिला उद्यमिता से संबंधित द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित कर प्रतिशत एवं तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह अध्ययन किया गया है कि स्वदेशी महिला उद्यमिता किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को मजबूत बनाती है।

विश्लेषण

सैद्धांतिक एवं नीतिगत पृष्ठभूमिः

आत्मनिर्भर भारत अभियान की अवधारणा

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त किया जाता है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि हो सके। यह अभियान पाँच प्रमुख स्तंभों–अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित है, जो भारत के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। इसके अंतर्गत "वोकल फॉर लोकल" की

नीति के माध्यम से स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग तथा प्रचार को प्रोत्साहित किया गया है। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों पर देखा गया है, क्योंकि उन्हें अपने पारंपरिक और स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन, विपणन और आय में वृद्धि के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

दमोह जिले की संरचनात्मक विशेषताएँ

दमोह जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख कृषि–प्रधान जिला है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण गतिविधियों पर आधारित है। यहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत अधिक होने के कारण अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन और छोटे पारिवारिक व्यवसायों पर निर्भर हैं। जिले में बड़े उद्योगों का विकास सीमित है, इसलिए स्थानीय स्तर पर छोटे उद्यम, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यवसाय ही आजीविका के प्रमुख साधन बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में महिलाओं की श्रम सहभागिता विशेष रूप से पारिवारिक और स्थानीय उद्यमों में अधिक दिखाई देती है। महिलाएँ कृषि कार्य, पशुपालन, हस्तशिल्प तथा घरेलू उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार जिले की सामाजिक–आर्थिक संरचना में स्वदेशी महिला उद्यमिता स्थानीय संसाधनों के उपयोग और रोजगार सृजन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की एक प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है।

स्वदेशी महिला उद्यमिता का आर्थिक विश्लेषण

(I) आय एवं रोजगार पर प्रभाव

स्व–सहायता समूहों के माध्यम से संचालित छोटे उत्पादन कार्योंकृजैसे पापड़, अचार, मसाले, अगरबत्ती निर्माण, डेयरी कार्य और सिलाई–कढ़ाई ने ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाएँ घर या समूह स्तर पर उत्पादन कर स्थानीय बाजारों में अपने उत्पाद बेच रही हैं। इससे उनकी नियमित आय के स्रोत विकसित हुए और आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे समूहों में शामिल महिलाओं की मासिक आय में लगभग 30–50% तक वृद्धि देखी गई है। कुछ सफल स्व–सहायता समूहों और उद्यम इकाइयों में उत्पादन और बाजार की मांग बढ़ने के कारण महिलाओं की आय लगभग दोगुनी भी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, परिवार की आय में योगदान बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला।

आय में परिवर्तन

आय स्तर	अभियान से पूर्व (%)	अभियान के बाद (%)
₹3000 से कम	48%	12%
₹3000–₹6000	37%	46%
₹6000 से अधिक	15%	42%

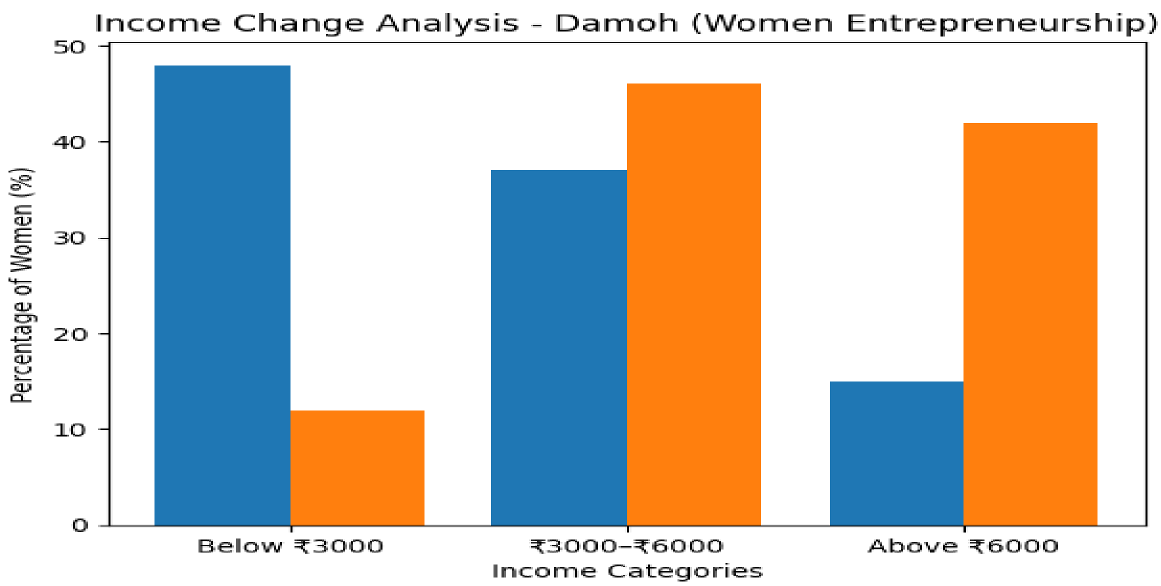

विश्लेषण

प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद महिलाओं की आय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अभियान से पूर्व लगभग 48% महिलाओं की मासिक आय ₹3000 से कम थी, जो अभियान के बाद घटकर 12% रह गई। यह कमी दर्शाती है कि कम आय वर्ग की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।इसी प्रकार ₹3000–₹6000 आय वर्ग में महिलाओं का प्रतिशत 37% से बढ़कर 46% हो गया, जो मध्यम आय वर्ग में वृद्धि को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ₹6000 से अधिक आय वर्ग में देखा गया, जहाँ महिलाओं का प्रतिशत 15% से बढ़कर 42% हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि स्व–सहायता समूहों, सरकारी योजनाओं और उद्यमिता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रोजगार सृजन

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता ने केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। स्व–सहायता समूहों और छोटे घरेलू उद्योगों के माध्यम से महिलाएँ पापड़, अचार, मसाले, अगरबत्ती निर्माण, डेयरी, बुनाई, सिलाई–कढ़ाई और हस्तशिल्प जैसे कार्यों में उत्पादन गतिविधियाँ संचालित करती हैं। इन उद्यमों के विस्तार के साथ–साथ कई समूहों ने अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी कार्य में शामिल किया, जिससे स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हुआ। इस प्रक्रिया से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट उत्पन्न हुआ, अर्थात एक महिला उद्यमी के कार्य से कई अन्य लोगों को भी आय और रोजगार के अवसर मिलने लगे। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आई बल्कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। परिणामस्वरूप परिवार की आय में वृद्धि, स्थानीय बाजारों की सक्रियता और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को भी मजबूती मिली।

रोजगार सृजन

रोजगार स्थिति	प्रतिशत
स्वयं रोजगार	100%
1–2 अन्य महिलाओं को रोजगार	44%
3 से अधिक रोजगार	12%

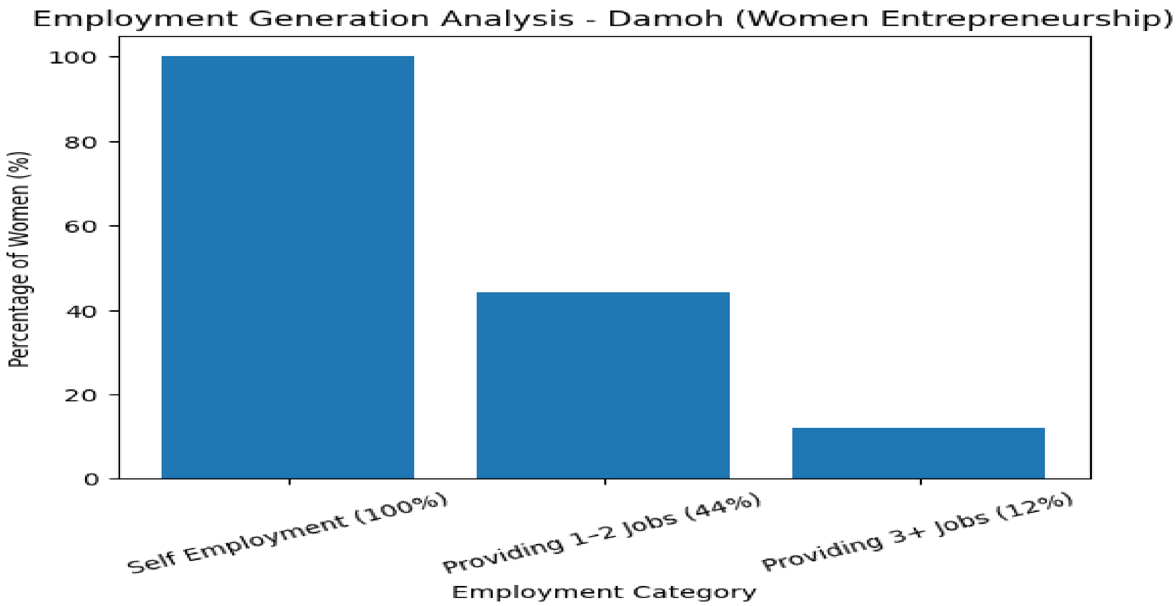

विश्लेषण

प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि महिला उद्यमिता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की रोजगार स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। अध्ययन के अनुसार 100% महिलाएँ स्वयं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्यमिता ने

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है।इसके अतिरिक्त लगभग 44% महिलाओं ने 1–2 अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान किया, जो दर्शाता है कि महिला उद्यमिता केवल व्यक्तिगत आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है। वहीं 12% उद्यमियों ने 3 से अधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान किया, जो छोटे स्तर के उद्यमों के विस्तार और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन

सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता और संस्थागत ऋण प्राप्त होने लगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों को बैंक लिंकेज सुविधा प्रदान की गई, जिससे समूहों को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त होने लगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्होंने अपने छोटे व्यवसायोंकृजैसे सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प का विस्तार किया। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप महिलाओं के बैंक खाते सक्रिय हुए, वे औपचारिक बैंकिंग और ऋण प्रणाली से अधिक जुड़ीं तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। साथ ही, पहले जहाँ महिलाएँ अक्सर साहूकारों और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर रहती थीं, अब उनकी यह निर्भरता कम हो गई है। इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और उद्यमिता क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा

संकेतक	प्रतिशत
बैंक खाता धारक	92%
SHG के माध्यम से ऋण प्राप्त	68%
मुद्रा योजना के तहत ऋण	34%

विश्लेषण

प्रस्तुत आंकड़े महिलाओं की वित्तीय समावेशन की स्थिति को दर्शाते हैं। अध्ययन के अनुसार 92% महिलाएँ बैंक खाता धारक हैं, जो यह संकेत देता है कि अधिकांश महिलाएँ औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुकी हैं और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ी है। इसके अतिरिक्त 68% महिलाओं ने स्व–सहायता समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समूह आधारित वित्तीय व्यवस्था महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। के माध्यम से महिलाएँ छोटे–छोटे ऋण प्राप्त कर अपने उद्यम को प्रारंभ या विस्तारित कर रही हैं। वहीं 34% महिलाओं ने मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं को उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही है।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत दमोह जिले में स्वदेशी महिला उद्यमिता ने न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार सृजन तथा ग्राम स्तरीय सतत विकास को भी मजबूत आधार प्रदान किया है।

अतः महिला स्व–सहायता समूह दमोह जिले में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं। दमोह जिले में स्वदेशी महिला उद्यमिता ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना को जमीनी स्तर पर सशक्त रूप से लागू किया है। महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों का विकास हुआ, जिससे महिलाओं की आय, बचत और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। इसके साथ ही, महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों, बच्चों की शिक्षा और पंचायत गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी, जो सामाजिक सशक्तिकरण का संकेत है। स्थानीय उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए।

समग्र रूप से, दमोह जिले में स्वदेशी महिला उद्यमिता आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण और सतत ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है, जो आत्मनिर्भर भारत के

उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ

Government of India. (2020). Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package. Ministry of Finance.

International Labour Organization (2020). Women in Entrepreneurship Development Report.

Ministry of Electronics and Information Technology. (2021). Digital India programme report. Government of India..

Ministry of Rural Development. (2021). Self Help Groups and Women Empowerment Report.

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2022). Annual report 2021–22. Government of India.

NITI Aayog. (2021). Women Entrepreneurship Platform report. Government of India.

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2021). SHG-Bank Linkage Programme Report.

National Bank for Agriculture and Rural Development (2021). SHG–Bank Linkage Programme Report.

National Bank for Agriculture and Rural Development. (2021). Status of Microfinance in India. NABARD.

NABARD. (2022). Status of SHG-bank linkage programme in India. NABARD.

National Rural Livelihoods Mission (NRLM). (2022). Annual Progress Report.

National Rural Livelihoods Mission (2022). Annual Progress Report.

National Rural Livelihoods Mission. (2022). Annual Report 2021–22. Ministry of Rural Development, Government of India.

Pradhan Mantri Mudra Yojana. (2021). PMMY Progress Report. Ministry of Finance, Government of India.

Reserve Bank of India. (2022). Report on Trend and Progress of Banking in India. RBI Publications.

World Bank. (2021). Women and economic growth. World Bank Publications.